

(1979) 09 पी एंड एच सीके 0031।

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में

केस नंबर : 1975 का आयकर संदर्भ संख्या 64

आयकर आयुक्त

अपीलार्थी

बनाम

राम सिंह हरमोहन सिंह

प्रतिवादी

निर्णय की तिथि: 24-09-1979

संदर्भित अधिनियम:

- आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 139 (1), धारा 148, धारा 271 (1)

उद्धरण: (1980) 1 आईएलआर (पी एंड एच) 220: (1980) 121 आईटीआर 381

माननीय न्यायाधीश: एस.एस. संधावालिया, सी.जे. गोकल चंद मित्तल, जे; डी.एस. तेवतिया,
जे।

बेंच: पूर्ण पीठ

एडवोकेट: डीएन अवस्थी, बीके झिंगन, भागीरथ दास, एसके हीराजी, बीके गुप्ता,

अंतिम निर्णय:

निर्णय

आयकर

अधिनियम

, 1961 की धारा 256 (1) (जिसे बाद में "अधिनियम" कहा जाता है) के इस संदर्भ में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, अमृतसर पीठ ने राय के लिए निम्नलिखित प्रश्न हमारे पास भेजे हैं:

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल का यह कहना सही था कि 1 अप्रैल, 1968 से इसके संशोधन से पहले मौजूद धारा 271 (1) (iii) के प्रावधान वर्तमान मामले पर लागू होंगे?

2. मेसर्स राम सिंह हरमोहन सिंह, अमृतसर (जिसे बाद में "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित किया गया) के आकलन वर्ष 1963-64 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, आईटीओ ने करदाता की कुल आय के लिए निम्नलिखित राशियों को शामिल किया जो करदाता के खातों में नकद क्रेडिट के रूप में दिखाई देती हैं:

रु।

(i) मेसर्स अमीर चंद मोती राम 42,000

(ii) मेसर्स बी मोहन सिंह एंड संस, 20,000

(iii) मेसर्स के नाम पर ब्याज। अमीर चंद मोती राम 2,075

3. उक्त अधिकारी ने आय छिपाने के लिए अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत जुर्माना नोटिस जारी किया और चूंकि न्यूनतम जुर्माना 1,000 रुपये की राशि से अधिक था, इसलिए उन्होंने मामले को अधिनियम की धारा 274 (2) के तहत आयकर आईएसी को भेज

दिया। अपील करने पर एएसी ने मेसर्स अमीर चंद मोती राम के खाते में राशि को घटाकर 17,000 रुपये कर दिया, लेकिन मेसर्स बी मोहन सिंह एंड संस के खाते में 20,000 रुपये जोड़ने और मेसर्स अमीर चंद मोती राम के खाते में 2,075 रुपये की ब्याज राशि जोड़ने को बनाए रखा।

आईएसी ने 15 मार्च, 1971 के अपने आदेश के तहत करदाता को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत करदाता पर 38,592 रुपये का जुर्माना लगाया।

आईएसी के आदेश से असंतुष्ट करदाता ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की। उक्त ट्रिब्यूनल ने माना कि मेसर्स अमीर चंद मोती राम के खाते में 17,000 रुपये के नकद क्रेडिट के संबंध में कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा इस अतिरिक्त को हटा दिया गया था। हालांकि, मेसर्स बी मोहन सिंह एंड संस के खाते में नकद क्रेडिट के रूप में 20,000 रुपये जोड़ने के संबंध में लगाए गए दंड को बनाए रखा गया था। जुर्माने की मात्रा के बारे में न्यायाधिकरण ने पाया कि आय का मूल रिटर्न करदाता ने 21 अप्रैल, 1967 से पहले दाखिल किया था और इस तरह एक अप्रैल, 1968 से पहले मौजूद जुर्माने के प्रावधान इस मामले पर लागू होते हैं। इस मामले को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने जुर्माना 30 प्रतिशत तय किया। (ii) अपील में अंतिम रूप से निर्धारित आय पर लगने वाले कर से बचने की मांग की गई है।

6. पक्षों के बीच यह आम आधार है कि यदि करदाता का रिटर्न, जिसमें आय को कथित रूप से छिपाया गया है, 1 अप्रैल, 1968 से पहले दाखिल किया गया था, तो जुर्माना लगाने योग्य कर की राशि से बचना होगा, और यदि रिटर्न उपरोक्त तिथि के बाद दाखिल किया गया था, जुर्माना उस आय के संदर्भ में होगा जिसे छिपाया जाना चाहिए। यह भी विवादित नहीं है कि अधिनियम की धारा 148 के तहत एक नोटिस के जवाब में करदाता ने 19 फरवरी, 1969 को

एक और रिटर्न दाखिल किया, जो अधिनियम की धारा 139 के तहत 21 अप्रैल, 1967 को उसके द्वारा दायर रिटर्न की सटीक प्रति थी।

7. राजस्व की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में दायर रिटर्न, यदि गलत पाया जाता है, तो कानून की सरल भाषा पर धारा 271 (1) (सी) के प्रावधानों को भी आकर्षित करता है। दूसरी ओर, करदाता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि मूल्यांकन एक विशेष वर्ष से संबंधित है और क्या किसी करदाता ने आय का विवरण छिपाया है या ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया है, यह केवल उस वर्ष के लिए आयकर के आकलन के उद्देश्य से करदाता द्वारा दायर मूल रिटर्न के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है। और चूक, यदि कोई हो, उस तारीख को किया गया था जब वह रिटर्न दाखिल किया गया था और केवल उस तारीख को लागू दंड प्रावधान आकर्षित होते हैं।

8. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 146 और 147 सीपीसी के आदेश 9, नियम 13, और आदेश 47, नियम 1 के अनुरूप हैं, जो एक सिविल कोर्ट को एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने और नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार देता है। उचित परिश्रम के बाद क्रमशः एक पार्टी की जानकारी में नहीं था। तर्क यह दिया गया है कि एक बार जब एक मूल्यांकन फिर से खोल दिया जाता है, तो मूल कारण यह है कि दायर मूल रिटर्न में आय का सही विवरण था या नहीं और गलत विवरण प्रस्तुत करने के बारे में निष्कर्ष ऐसे मूल रिटर्न के आधार पर दिया जाना चाहिए। इस दलील के समर्थन में [आयकर आयुक्त बनाम गोपाल कृष्ण सिंघानिया](#) पर भरोसा जताया जाता है।

9. राजस्व की ओर से हमारा ध्यान [श्रीमती कमला वती बनाम आयकर आयुक्त \(सेंट्रल\), पटियाला](#) मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के एक निर्णय की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 273 में दिखाई देने वाले "नियमित मूल्यांकन" शब्द अधिनियम की धारा 147 के तहत विचार किए गए पुनर्मूल्यांकन के दायरे में नहीं आते हैं।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि धारा 147 के तहत कार्यवाही अलग-अलग कार्यवाही है, तो अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के अनुसार दायर कोई भी रिटर्न अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) में निहित दंड प्रावधानों को आकर्षित करेगा। उस मामले में, हालांकि, डिवीजन बेंच का ध्यान आयकर आयुक्त बनाम गोपाल कृष्ण सिंघानिया की ओर आकर्षित नहीं किया गया था। यह मामला कठिनाई से मुक्त नहीं है और बड़ी संख्या में मामलों में उत्पन्न होने की संभावना है और हमारी राय में पूर्ण पीठ द्वारा अधिक उचित रूप से निर्णय लिया जा सकता है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश प्राप्त किए जाएं,

पूर्ण पीठ का फैसला

न्यायमूर्ति डी.एस. एवतिया ।

10. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256 (1) (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय की राय के लिए संदर्भित प्रश्न है:

"क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल का यह मानना सही था कि अधिनियम की धारा 271 (1) (iii) के प्रावधान, जो 1 अप्रैल, 1968 से इसके संशोधन से पहले मौजूद थे, वर्तमान मामले पर लागू होंगे?"

11. प्रारंभ में संदर्भ को एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था, जिसने बदले में इसे एक बड़ी पीठ को भेज दिया और इस तरह मामला हमारे सामने है।

12. पूछे गए प्रश्न पर विचार करने से पहले, उक्त प्रश्न पर प्रभाव डालने वाले आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

13. मैसर्स राम सिंह हरमोहन सिंह, अरनृत्सर (जिसे बाद में "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित किया गया) के आकलन वर्ष 1963-64 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, आईटीओ ने

करदाता की कुल आय की गणना निम्नलिखित राशियों को जोड़कर की, जिसे उनके खाते की पुस्तकों ने नकद क्रेडिट के रूप में दिखाया:

रु।

1. मेसर्स अमीर चंद मोती राम 42,000
2. मेसर्स बी. मोहन सिंह एंड संस 20,000
3. मेसर्स के नाम पर रुचि। अमीर चंद 2,075

मोती राम

14. अपील पर, एएसी ने मेसर्स अमीर चंद मोती राम के खाते में वृद्धि को घटाकर 17,000 रुपये कर दिया, लेकिन मेसर्स बी मोहन सिंह एंड संस के खाते में 20,000 रुपये की वृद्धि और मेसर्स अमीर चंद मोती राम के खाते में 2,075 रुपये की ब्याज राशि जोड़ने को बनाए रखा।

15. उक्त राशि को आय छिपाने के रूप में मानते हुए, आईटीओ ने आय छिपाने के लिए अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत जुर्माना नोटिस जारी किया और चूंकि जुर्माना 1,000 रुपये से अधिक हो गया, इसलिए मामले को अधिनियम की धारा 274 (2) के तहत आयकर के आईएसी को भेज दिया गया। आईएसी ने 15 मार्च, 1971 के अपने आदेश के तहत करदाता को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद उस पर अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) (iii) के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1968 को 38,592 रुपये का जुर्माना लगाया। 1969 में जब धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में करदाता द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया था, जिसमें मूल रिटर्न में दिखाई गई आय को दोहराया गया था।

16. एक अपील पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि मेसर्स अमीर चंद मोती राम के खाते में 17,000 रुपये के नकद क्रेडिट के संबंध में कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, उक्त अतिरिक्त को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा एएसी के आदेश से अपील पर हटा दिया गया है। बी. मोहन सिंह एंड संस के खाते में नकद क्रेडिट से संबंधित 20,000 रुपये जोड़ने के संबंध में जुर्माना लगाया गया था और इसलिए इसे बनाए रखा गया था। जुर्माने की मात्रा की गणना अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) (iii) के दंड प्रावधानों के संदर्भ में की गई थी, क्योंकि यह 1 अप्रैल, 1968 से पहले अस्तित्व में था, क्योंकि इसके अनुसार, छिपाने का अपराध तब किया गया था जब करदाता द्वारा आय का मूल रिटर्न दाखिल किया गया था और यह 21 अप्रैल को था। 1967. उपरोक्त दृष्टिकोण के प्रकाश में, ट्रिब्यूनल ने जुर्माना 30 प्रतिशत तय किया। (ii) अपील में अंतिम रूप से निर्धारित आय पर लगने वाले कर से बचने की मांग की गई है।

17. पक्षकार इस तथ्य के संबंध में एक-दूसरे से भिन्न नहीं हैं कि जिस दिन यानी 21 अप्रैल, 1967 को करदाता द्वारा मूल रिटर्न दाखिल किया गया था, उस दिन जुर्माने की मात्रा कर-परिहार आधार का अनुसरण करती थी, अर्थात्, इसमें अपनी आय को छिपाकर बचने के लिए की जाने वाली कर की मात्रा का संदर्भ था और जिस दिन नोटिस के जवाब में रिटर्न दाखिल किया गया था। इस अधिनियम की धारा 148 अर्थात् 19 फरवरी, 1969 को दायर की गई थी, जिसमें जुर्माने की मात्रा के बाद आय से बचने वाले आधार का अनुसरण किया गया था, अर्थात् जुर्माने की मात्रा की गणना छिपी हुई आय की मात्रा के संदर्भ में की जानी थी। छिपी हुई आय के संबंध में जुर्माना लगाने के लिए कर अधिकारियों को अधिकृत करने वाले प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में हैं (1 अप्रैल, 1968 से पहले):

(1) यदि आयकर अधिकारी या अपीलीय सहायक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति-

(क) बिना किसी उचित कारण के वह कुल आय की विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिसे उसे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 139 या धारा 148 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए नोटिस द्वारा प्रस्तुत करना अपेक्षित था या उचित कारण के बिना अनुमत समय के भीतर और धारा 139 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित तरीके से या ऐसे नोटिस द्वारा प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जैसा भी मामला हो, या.....

(ग) अपनी आय का विवरण छुपाया है या ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया है, वह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में भुगतान करेगा,--

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामलों में, उसके द्वारा देय कर की राशि, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, दो प्रतिशत के बराबर राशि। (ग) प्रत्येक माह के लिए कर, जिसके दौरान चूक जारी रही, लेकिन कुल पचास प्रतिशत से अधिक नहीं। कर के बारे में ..."

18. उप-खंड (iii), जैसा कि यह 1 अप्रैल, 1968 से पहले अस्तित्व में था, अर्थात्, जिस तारीख को मूल रिटर्न दाखिल किया गया था, वह इन शर्तों में था:

(iii) खंड (ग) में निर्दिष्ट मामलों में, उसके द्वारा देय किसी कर के अतिरिक्त, एक राशि जो बीस प्रतिशत से कम नहीं होगी। लेकिन जो कर की राशि के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगा, यदि कोई हो, जिसे टाला जा सकता था यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा लौटाई गई आय को सही आय के रूप में स्वीकार किया गया होता। "

19. अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) को 1 अप्रैल, 1968 के वित्त अधिनियम द्वारा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था:

"(iii) खंड (सी) में निर्दिष्ट मामलों में, उसके द्वारा देय किसी कर के अलावा, एक राशि जो कम नहीं होगी, लेकिन जो दो गुना से अधिक नहीं होगी, उस आय की राशि जिसके संबंध में विवरण छिपाया गया है या गलत विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

20. इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि करदाता द्वारा दाखिल रिटर्न में आय को छिपाना अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के प्रावधानों को आकर्षित करता है, न कि तब जब करदाता द्वारा रिटर्न दाखिल करने से इनकार करके वास्तविक आय को छिपाने की मांग की जाती है। इस संबंध में वेंकटरमैया जे. ने अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मैसूर बनाम सीवी बागलकोटी एंड संस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं, जिनके संबंध में, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लाभ के साथ उद्धृत किया जा सकता है:

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आय का विवरण छिपाने या ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने का अपराध किया जाता है। केवल रिटर्न दाखिल न करने को या तो आय को छिपाना नहीं माना जा सकता है जो कर के लिए उत्तरदायी है या इसके बारे में गलत विवरण प्रस्तुत करना (एस संथोसा नाडर बनाम प्रथम अतिरिक्त आयकर अधिकारी, तूतीकोरिन और अन्य)।

21. इस बात पर न्यायिक सहमति है कि आय को छिपाने के लिए अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के दंडात्मक प्रावधानों के तहत प्रावधान तब होते हैं जब करदाता द्वारा रिटर्न दाखिल किया जाता है।

22. चूंकि आय छिपाने का अपराध दंडनीय प्रकृति का होता है और चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कोई व्यक्ति केवल उतनी ही सजा के लिए उत्तरदायी होता है जितना अपराध किए जाने के समय दिया जा सकता था, इसलिए उस तारीख को तय करना आवश्यक हो जाता है जिस पर छिपाने का अपराध कहा जा सकता है।

23. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, आय को छिपाना तब होता है जब आय के विवरण को छिपाते हुए या आय का गलत विवरण देते हुए रिटर्न दाखिल किया जाता है। जहां आय

के विवरण को छिपाने या आय का गलत विवरण देने वाला केवल एक ही रिटर्न दाखिल किया जाता है, वहां आय छिपाने के अपराध की तारीख तय करने में कोई कठिनाई नहीं होती है क्योंकि यह वह तारीख होगी जिस दिन करदाता द्वारा ऐसा रिटर्न दाखिल किया जाता है, लेकिन जहां एक करदाता द्वारा एक से अधिक रिटर्न दाखिल किए जाते हैं जिसमें सही आय नहीं दिखाई गई थी और ये रिटर्न होते हैं। अलग-अलग तारीखों पर दायर किया जाता है और उन तारीखों पर संचालित कानून द्वारा प्रदान की गई सजा, इसकी गंभीरता में भिन्न होती है, फिर यह सवाल कि क्या आय छिपाने का अपराध एक या दूसरी तारीख को या दोनों तारीखों पर किया गया है, महत्व रखता है और कुछ कठिनाइयों को प्रस्तुत करता है।

24. ऊपर उठाए गए प्रश्नों से निपटने से पहले, आइए पहले आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो रिटर्न दाखिल करने की परिकल्पना करते हैं। ये अधिनियम की धारा 139 (1), (2) और (5) और धारा 148 (1) हैं जो निम्नलिखित शब्दों में हैं:

(1) प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन योग्य है, अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभारयोग्य नहीं है, तो वह पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का रिटर्न निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा और निर्धारित तरीके से सत्यापित करेगा और ऐसे अन्य विवरण निर्धारित करेगा। जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है--...

(2) ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जो आयकर अधिकारी की राय में, इस अधिनियम के अधीन कर योग्य है, चाहे वह अपनी कुल आय पर हो या पिछले वर्ष के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय पर, आयकर अधिकारी, संगत मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से पहले, उसे एक नोटिस दे सकता है, जिसमें उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, नोटिस जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उसकी आय या पिछले वर्ष के दौरान ऐसे अन्य व्यक्ति

की आय की रिटर्न, निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से सत्यापित और ऐसे अन्य विवरण निर्धारित करना जो निर्धारित किए जा सकते हैं:

(5) यदि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत रिटर्न दाखिल करने वाले किसी व्यक्ति को उसमें कोई चूक या कोई गलत विवरण मिलता है, तो वह मूल्यांकन किए जाने से पहले किसी भी समय संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है।

(1) धारा 147 के तहत आकलन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना करने से पहले, आयकर अधिकारी करदाता को एक नोटिस देगा जिसमें धारा 139 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस में शामिल सभी या किन्हीं आवश्यकताओं को शामिल किया जा सकता है; और इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे जैसे कि नोटिस उस उप-धारा के तहत जारी किया गया नोटिस था।

25. उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि कानून की बाध्यता के तहत एक करदाता को धारा 139 (1) और (2) और धारा 148 के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है। वह धारा 139(5) के तहत स्वेच्छा से संशोधित रिटर्न भी दाखिल कर सकता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या कोई करदाता किसी दिए गए वर्ष के लिए एक से अधिक रिटर्न दाखिल करेगा? उत्तर हां में है, क्योंकि वह धारा 139 (1) के तहत या जब आवश्यक हो तो धारा 139 (2) के तहत एक रिटर्न दाखिल कर सकता है। वह स्वेच्छा से धारा 139 (5) के तहत अतिरिक्त रिटर्न दाखिल कर सकता है। अधिनियम की धारा 148 के तहत आवश्यक होने पर वह एक और रिटर्न भी दाखिल कर सकता है। कोई यह पूछ सकता है कि क्या ऐसा करदाता हर बार अपराध करता है जब उसने वैधानिक बाध्यता के तहत उन दो रिटर्न दाखिल किए, एक मूल और दूसरा धारा 148 के तहत और जब उसने स्वेच्छा से धारा 139 (5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल किया।

26. इस तर्क का तर्क कि आय को छिपाना रिटर्न दाखिल करते समय होता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हर बार जब कोई करदाता अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (5) द्वारा परिकल्पित स्वेच्छा से रिटर्न दाखिल करता है और जो रिटर्न मूल रिटर्न में संशोधन का चरित्र प्राप्त नहीं करता है जैसा कि वर्तमान में दिखाया जाएगा या उप-धारा (1) और (2) द्वारा परिकल्पित वैधानिक बाध्यता के तहत होता है। अधिनियम की धारा 139 और धारा 148 के तहत, वह आय छिपाने का अपराध करता है और यदि ऐसे रिटर्न की तारीखें बदलती हैं, तो आय छिपाने का प्रत्येक अपराध छिपाने के ऐसे अन्य अपराध से स्वतंत्र है, ऐसे अपराध के लिए दंड की मात्रा में उक्त अपराध के होने की तारीख पर प्रचलित कानून द्वारा निर्धारित दंड का संदर्भ होगा।

27. अब, अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (5) द्वारा परिकल्पित स्वैच्छिक रिटर्न की ओर मुड़ते हुए, यह देखा जा सकता है कि यह धारा 139 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत दायर मूल रिटर्न में अनजाने में चूक की आपूर्ति करता है या उसमें अनजाने में दिए गए किसी गलत बयान को सही करता है, इसमें मूल रिटर्न में संशोधन का चरित्र है और, इसलिए, मूल वापसी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब यह पाया जाता है कि मूल रिटर्न में हुई चूक का इरादा सुधार या उसमें किसी कथित गलत विवरण का सुधार, वास्तव में आय को छिपाने के उद्देश्य से किया गया था और आय को छिपाया जाता है, जो इतना छुपाया नहीं जाता यदि मूल रिटर्न को उसी रूप में रहने दिया गया होता और अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (5) के तहत रिटर्न, यदि इसे दाखिल नहीं किया गया होता, तो मेरे विचार से इस तरह के संशोधित रिटर्न को दाखिल करने के माध्यम से हुई आय को छिपाना अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा और अपराध होने की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन इस तरह का संशोधित रिटर्न दाखिल किया गया था, न कि इस तरह के मूल रिटर्न की तारीख।

28. इस अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के संदर्भ में यदि रिटर्न में आय को छिपाना अपराध है और करदाता एक से अधिक बार छिपाने का प्रभाव डालता है, तो क्या उसे किसी दिए गए वर्ष की आय छिपाने के एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित किया जा सकता है? क्या ऐसे मामले में, दोहरे खतरे का सिद्धांत आकर्षित नहीं होगा?

29. मेरी राय में, यद्यपि यह सच है कि किसी दिए गए आकलन वर्ष की आय को रिटर्न में छिपाना अपराध है, फिर भी यह सोचना गलत धारणा है कि बार-बार किए गए उक्त अपराध में केवल एक ही सजा होगी और वह भी वह जो उस तारीख को संचालित कानून द्वारा प्रदान की गई थी जब उक्त अपराध पहली बार किया गया था।

30. दोहरे खतरे का सिद्धांत केवल एक ऐसे मामले की ओर आकर्षित होता है जहां किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दो बार दंडित करने की मांग की जाती है, लेकिन जहां ऐसा नहीं है, यानी, जहां एक निश्चित अपराध जिसके लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना और दंडित किया जाना है, पहले अपराध से अलग अपराध है, तब दोहरे खतरे के सिद्धांत की कोई प्रयोज्यता नहीं होगी। उदाहरण के लिए, झूठी गवाही का एक मामला लें, किसी दिए गए कार्यवाही में एक व्यक्ति किसी दिए गए तथ्य के संबंध में गलत बयान देता है। वह झूठी गवाही देने का अपराध करता है। यदि वह व्यक्ति जो पिछली कार्यवाही को जारी रखने वाला नहीं है, लेकिन पहले की कार्यवाही के पूरक के रूप में भिन्न है, उस तथ्य के बारे में फिर से गलत बयान देता है जिसके बारे में उसने पहले की कार्यवाही में गलत बयान दिया था, तो बाद में गलत बयान झूठी गवाही का एक स्वतंत्र अपराध माना जाएगा, हालांकि तथ्य जो दोनों बयानों में गलत तरीके से कहा गया है वह समान है।

31. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत परिकल्पित दंडात्मक प्रावधानों को विधायिका द्वारा गलत रिटर्न दाखिल करके वास्तविक आय को छिपाने की प्रवृत्ति का मुकाबला करने और निर्धारिती को अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (5) के प्रावधानों

का लाभ उठाते हुए या जब आवश्यक हो, सच्चाई के साथ सामने आने के लिए प्रेरित करने के लिए विधायिका द्वारा पेश किया गया था। अधिनियम की धारा 148 के तहत एक नोटिस। यदि यह विचार लिया गया है कि कोई करदाता मूल रिटर्न दाखिल करते समय केवल एक बार छिपाने का अपराध करता है, न कि जब वह अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के अनुपालन में आवश्यक होने पर वैधानिक मजबूरी में बाद में रिटर्न दाखिल करता है, तो करदाता को रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, न कि रिटर्न दाखिल न करने के लिए दंड का जोखिम उठाने के बजाय। मूल रिटर्न दाखिल करते समय अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के संदर्भ में आय छिपाने के अपराध के लिए दंड के अतिरिक्त रिटर्न जो जुर्माना होगा। मेरी राय में विधायिका का इरादा ऐसी कोई खामी छोड़ने का नहीं था और इसलिए उसने परिकल्पना की थी कि हर बार जब कोई करदाता वैधानिक बाध्यता के तहत या स्वेच्छा से अपनी आय का झूठा रिटर्न दाखिल करता है, तो वह अलग से दंडनीय अपराध करता है।

32. करदाता के वकील श्री भागीरथ दास ने मुख्य रूप से आयकर आयुक्त बनाम राम अचल राम सेवक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया, जिसका अनुसरण आयकर आयुक्त बनाम कृष्ण सुभाष करण और अतिरिक्त आयकर आयुक्त बनाम मेवा लाल संकठा प्रसाद में रिपोर्ट किए गए इसके बाद के दो फैसलों में किया गया था । अपने प्रस्ताव के समर्थन में कि ऐसे मामले में जहां मूल रिटर्न के अलावा, अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के अनुसरण में रिटर्न दाखिल किया जाता है, जिसमें संबंधित आकलन वर्ष के लिए वास्तविक आय का भी खुलासा नहीं किया जाता है, करदाता आय को छिपाने का केवल एक अपराध करता है और वह भी उस तारीख को जब उसने मूल रिटर्न दाखिल किया था। इसलिए, दंड की मात्रा की गणना मूल रिटर्न दाखिल करने की तारीख पर प्रचलित कानून द्वारा नियंत्रित की जाएगी। विद्वान वकील द्वारा आयकर आयुक्त बनाम राम अचल राम सेवक के निम्नलिखित उद्धरण की ओर ध्यान दिलाया गया था, जिसमें अदालत के दृष्टिकोण के समर्थन में तर्क शामिल था (पृष्ठ 150):

इसमें कहा गया है, 'सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे मामले में जहां किसी करदाता ने अपनी आय का ब्योरा छिपाया है या मूल रिटर्न में ऐसी आय का गलत ब्योरा दिया है और इस तरह वह जुर्माने का पात्र बनता है, धारा 148 के तहत नोटिस के अनुपालन में रिटर्न दाखिल करने पर आय का ब्योरा छिपाने या गलत तरीके से देने के लिए दूसरा जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग के वकील द्वारा उठाए गए तर्क की स्वीकृति के नतीजों की जांच विशेष मामलों के संदर्भ में की जा सकती है। शुरुआत में, हम एक ऐसे मामले को लेंगे जहां एक करदाता ने अपनी आय का विवरण छिपाया है या अपने मूल रिटर्न में ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया है और धारा 148 के तहत नोटिस के अनुपालन में दायर रिटर्न में भी। यदि विभाग के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो करदाता दो दंडों के लिए उत्तरदायी होगा, एक मूल रिटर्न के संबंध में विवरण छिपाने या गलत प्रस्तुत करने के संबंध में, और दूसरा के संबंध में, जब उसने धारा 148 के तहत नोटिस के अनुपालन में रिटर्न दाखिल किया था, और आयकर अधिकारी जो अधिकतम जुर्माना लगा सकता है, वह छिपी हुई आय की राशि का दोगुना हो सकता है। प्रत्येक अवसर के साथ, जिसके परिणामस्वरूप छिपाने के लिए कुल जुर्माना छिपी हुई आय की राशि का चार गुना होगा। हमें नहीं लगता कि इस तरह के परिणाम का इरादा विधायिका द्वारा किया गया था। इसके अलावा, यदि किसी करदाता ने अपनी आय का विवरण छिपाया है या एक बार ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि वह उसी कार्य को फिर से दोहराता है, तो उसी आय के बारे में नए सिरे से छिपाया या गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस तर्क को स्वीकार करने में अन्य कठिनाइयां हैं। मान लीजिए कि किसी करदाता ने 1 अप्रैल, 1964 से पहले दाखिल किए गए मूल रिटर्न में 50,000 रुपये की आय के संबंध में गलत विवरण छिपाया या प्रस्तुत किया है, जबकि धारा 148 के तहत नोटिस के अनुपालन में दाखिल रिटर्न में कोई छिपाव नहीं है या केवल 25,000 रुपये की जानकारी छिपाई गई है। यदि धारा 148 के तहत कार्यवाही के अनुसरण में जुर्माना तय करने के उद्देश्य से संबंधित रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो पहले मामले में कोई जुर्माना

नहीं लगाया जा सकता है, जबकि दूसरे मामले में, जुर्माना कम हो जाएगा क्योंकि दूसरे रिटर्न में छिपाना मूल रिटर्न की तुलना में कम है। हमें ऐसा लगता है कि विधायिका का इरादा ऐसे करदाता को पहले मामले में छोड़ देने या दूसरे मामले में कम जुर्माना लगाने का नहीं था।

33. संबंध में, मैं पूर्वोक्त निर्णयों में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं दो झूठे रिटर्न दाखिल करने को स्वतंत्र अपराध मानता हूँ, जिसमें प्रत्येक अपराध के लिए अलग-अलग दंड होता है, जैसा कि मैंने पहले ही निर्णय के पहले भाग में देखा था। करदाता के वकील ने तब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से समर्थन प्राप्त करने की मांग की, जिसे एनए मालबारी एंड ब्रदर्स के रूप में रिपोर्ट किया गया था। **बनाम आयकर आयुक्त, मुंबई**, उनके निवेदन के लिए कि एक ही छिपाने के संबंध में, एक व्यक्ति को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। उस मामले में तथ्य यह था कि करदाता ने अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत दायर रिटर्न में अपनी बैंक शाखा की फर्म के व्यावसायिक मुनाफे को शामिल नहीं किया था। करदाता फर्म को उन खातों का उत्पादन करना था जो उसने पेश नहीं किए थे। आईटीओ ने अनुमान लगाया कि उक्त बैंक शाखा का 37,500 रुपये का मुनाफा बचा है और मूल्यांकन पूरा किया और उसी दिन आय छिपाने के लिए जुर्माना लगाने की कार्यवाही शुरू की और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इस बीच, अगले वर्ष के लिए मूल्यांकन कार्यवाही में करदाता ने बैंक शाखा की लेखा पुस्तिकाएं पेश कीं, जिसमें खुलासा किया गया कि करदाता ने पिछले आकलन वर्ष के लिए 1,25,520 रुपये का लाभ कमाया था, जिसके लिए मूल्यांकन पूरा हो गया था। आईटीओ ने पिछले आकलन वर्ष के संबंध में भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (जो आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 148 के बराबर है) की धारा 34 के तहत एक नोटिस जारी किया और करदाता ने उक्त पिछले वर्ष के 1,25,520 रुपये के सही मुनाफे को दिखाते हुए एक रिटर्न प्रस्तुत किया। इसके बाद आईटीओ ने भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 28 (3) (जो आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) के बराबर है) के तहत

एक नोटिस जारी किया और मूल रिटर्न में आय छिपाने के लिए 68,501 रुपये का दूसरा जुर्माना लगाया।

34. ट्रिब्यूनल ने 37,500 रुपये की भागने वाली आय से संबंधित 20,000 रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया, लेकिन 68,501 रुपये के जुर्माने की पुष्टि की। अन्य बातों के साथ-साथ उनके लॉर्डशिप के समक्ष यह तर्क उठाया गया था कि जुर्माना लगाने का दूसरा आदेश अवैध था क्योंकि इसी को छिपाने के संबंध में आईटीओ के पास दूसरा आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जबकि पहला आदेश खड़ा था। उनके लॉर्डशिप ने उक्त विवाद का खंडन करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की (पृष्ठ 298, 299):

"हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह हो सकता है कि एक ही छिपाने के संबंध में दंड के दो आदेश नहीं टिकेंगे लेकिन यह अधिकार क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। इस धारा के तहत जुर्माने को उस कर की राशि से जोड़ा जाना चाहिए जो कर चोरी की गई होती यदि करदाता इसे छिपाने से बच जाता। इस मामले में एक अनुमान द्वारा आय का आकलन करने के बाद, आयकर अधिकारी ने उस अनुमान के आधार पर जुर्माना लगाया। बाद में, जब उन्होंने सही तथ्यों का पता लगाया और महसूस किया कि बहुत अधिक जुर्माना लगाया जा सकता था, तो वह पहले के आदेश को वापस लेने और उच्च जुर्माना लगाने का एक और आदेश पारित करने के हकदार थे।

35. करदाता के विद्वान वकील ने ऊपर दिए गए उनके लॉर्डशिप के रेखांकित हिस्से की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उस मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित तथ्यों के बयान से स्पष्ट होगा, निर्धारिती द्वारा छिपाने का केवल एक अपराध था; तब उन्होंने पहला रिटर्न फाइल किया था। अधिनियम की धारा 148 के तहत एक नोटिस के अनुसरण में दायर किए गए दूसरे रिटर्न में उन्होंने वास्तविक आय का स्पष्ट विवरण दिया था। इसलिए, करदाता ने 1,25,520 रुपये की अपनी आय को छिपाने का केवल एक अपराध किया, जबकि उसे न केवल

उक्त राशि को छिपाने के संबंध में दंडित किया गया, बल्कि 37,500 रुपये छिपाने के अलावा जो पहले के जुर्माना आदेश का विषय था, जिसके बारे में 20,000 रुपये की राशि जुर्माना के रूप में लगाई गई थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उनके लॉर्डशिप की रेखांकित टिप्पणियां उस मामले के तथ्यों के संदर्भ से संबंधित हैं, जहां वास्तव में अपराध केवल एक था और वह भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 34 के तहत दूसरे रिटर्न में करदाता द्वारा दायर मूल रिटर्न में वास्तविक आय को छिपाना था। 1922 (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के बराबर), वास्तविक आय का खुलासा किया गया था और उसने कोई अपराध नहीं किया था। उपरोक्त कारणों से, मेरा विचार है कि वर्तमान मामले में करदाता ने न केवल अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत मूल गलत रिटर्न दाखिल करने में आय को छिपाने का अपराध किया, बल्कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के अनुसरण में इसी तरह की झूठी रिटर्न दाखिल करने पर एक अलग और विशिष्ट अपराध भी किया। इसलिए, प्रत्येक अपराध के लिए अलग से दंडित किया जा सकता है।

36. यद्यपि निर्धारिती ने दो अलग-अलग और अलग-अलग अपराध किए हैं, जो दोनों के लिए अलग-अलग दंडित किए जाने योग्य हैं, फिर भी राजस्व अधिकारियों ने कानून के गलत दृष्टिकोण के तहत उसे अधिनियम की धारा 148 के तहत एक नोटिस के अनुसरण में गलत रिटर्न दाखिल करने के परिणामस्वरूप किए गए अंतिम अपराध के लिए दंडित किया। चूंकि यह बाद में अपराध ऐसे समय में किया गया था जब अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) (iii) के संशोधित प्रावधान लागू थे, जो "आय-टालने वाले आधार" दंड को आकर्षित करते थे, ट्रिब्यूनल ने मेरे विचार में यह कहते हुए गलती की कि करदाता ने मूल रिटर्न दाखिल करते समय छिपाने का केवल एक अपराध किया था (जो घटना अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) (iii) के संशोधन से पहले हुई थी) और जुर्माना लगाने में। मूल रिटर्न दाखिल करने की तारीख से लागू अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) (iii) के असंशोधित प्रावधानों के अनुसार इसकी मात्रा की गणना की गई थी।

37. परिणाम में, मैं निर्धारिती के विरुद्ध और राजस्व के पक्ष में संदर्भ का उत्तर देता हूं जिसमें कहा गया है कि निर्धारिती के मामले में जुर्माने की मात्रा को राजस्व अधिकारियों द्वारा उस कानून के अनुसार गणना योग्य माना गया था जिस दिन करदाता द्वारा अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के अनुसरण में दूसरा रिटर्न दाखिल किया गया था और ट्रिब्यूनल ने गलती की थी। राजस्व अधिकारियों के उक्त निर्णय को पलटना। लागत के साथ संदर्भ की अनुमति है।

गोकल चंद मित्तल, जे।

38. मुझे डी. एस. तेवतिया जे. द्वारा तैयार किए गए निर्णय को पढ़ने का लाभ मिला। मुझे खेद है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं।

39. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाता है) के संदर्भ में, निम्नलिखित प्रश्न इस न्यायालय की राय के लिए भेजा गया है:

"क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल कानून में सही था, यह मानते हुए कि अधिनियम की धारा 271 (1) (iii) के प्रावधान, जो 1 अप्रैल, 1968 से इसके संशोधन से पहले मौजूद थे, वर्तमान मामले पर लागू होंगे?"

40. हमारे निर्णय के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या पहला रिटर्न दाखिल करते समय प्रचलित कानून, चाहे वह स्वेच्छा से धारा 139 (1) के तहत दायर किया गया हो या अधिनियम की धारा 139 (2) के तहत आईटीओ के कहने पर, केवल लागू हो सकता है या क्या बाद में संशोधित प्रावधान, जो धारा 148 के तहत नोटिस के अनुसरण में रिटर्न दाखिल करते समय लागू था। अधिनियम की धारा 271 के तहत जुर्माना लगाने के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 10 के तहत लागू होगी।

41. उपर्युक्त बिंदु पर विचार करने के लिए, अधिनियम की धारा 271 (1) (iii) के इतिहास का पता लगाना आवश्यक होगा जो अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत किए गए चूक के लिए दंड की मात्रा को नियंत्रित करता है। उप-खंड (iii), जैसा कि यह 1 अप्रैल, 1968 से पहले अस्तित्व में था, निम्नानुसार था:

(iii) खंड (ग) में निर्दिष्ट मामलों में, उसके द्वारा देय किसी कर के अतिरिक्त, एक राशि जो बीस प्रतिशत से कम नहीं होगी। लेकिन जो कर की राशि के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगा, यदि कोई हो, जिसे टाला जा सकता था यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा लौटाई गई आय को सही आय के रूप में स्वीकार किया गया होता। "

42. उपखंड (iii) जैसा कि 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1976 तक लागू था, निम्नानुसार था:

(iii) संदर्भित मामलों में (खंड (ग) उसके द्वारा देय किसी कर के अतिरिक्त, एक राशि जो उससे कम नहीं होगी, लेकिन जो दो गुना से अधिक नहीं होगी, उस आय की राशि जिसके संबंध में विवरण छिपाया गया है या गलत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

43. 1 अप्रैल, 1976 से अस्तित्व में आया उप-खंड निम्नानुसार है:

(iii) खंड (ग) में निर्दिष्ट मामलों में, उसके द्वारा देय किसी कर के अतिरिक्त, एक राशि जो उसकी आय के विवरण को छिपाने या ऐसी आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने के कारण चोरी की जाने वाली कर की राशि से कम नहीं होगी, लेकिन जो दो गुना से अधिक नहीं होगी: ..."

44. उप-खंड (iii) का तुलनात्मक अध्ययन, जो तीन अलग-अलग समयों पर प्रचलित था, यह दर्शाता है कि पहला और तीसरा कर आधारित है जबकि दूसरा कर आधारित है। पहले और तीसरे में अंतर यह है कि पहले प्रावधान में न्यूनतम जुर्माना बीस प्रतिशत था। बच कर की अधिकतम राशि बच गए कर का $11/2$ गुना थी, जबकि तीसरे में न्यूनतम बच गए कर के

बराबर है और अधिकतम कर की राशि से दोगुना है। अतः, उपखंड (iii) का इतिहास यह दर्शाता है कि एक समय संसद ने कर से बचने के आधार पर जुर्माना निर्धारित करने के बारे में सोचा था और इसमें संशोधन किया गया था ताकि जुर्माने के आधार को आय से बचा जा सके और फिर से वर्तमान प्रावधान कर से बचने के आधार पर है, हालांकि जुर्माने का न्यूनतम और अधिकतम प्रतिशत जो लगाया जा सकता है उसे बढ़ा दिया गया है। अतः, न्यूनतम या अधिकतम जुर्माना क्या होना चाहिए और क्या इसे कर-परिहार आधारित या आय के आधार पर रोका जाना चाहिए, यह संसद को तय करना है। न्यायालयों को यह करना है कि वे अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करें और उन्हें सामंजस्यपूर्ण तरीके से लागू करें।

45. मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, इस मामले में कुछ स्वीकृत तथ्यों को संक्षेप में बताना आवश्यक होगा। जिस प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष से हम संबंधित हैं वह 1963-64 है। करदाता ने 21 अप्रैल, 1967 को अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत उक्त वर्ष के लिए अपना मूल रिटर्न दाखिल किया। इसके बाद, आईटीओ द्वारा अधिनियम की धारा 148 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था और उसके अनुसरण में, उन्होंने 19 फरवरी, 1969 को मूल रिटर्न की शब्दशः प्रति दायर की थी। अतः, निर्धारिती द्वारा 21 अप्रैल, 1967 के मूल विवरणी में जो जानकारी छिपाई गई थी, वह बाद की उक्त विवरणी में भी बनी रही।

46. किसी भी पक्ष द्वारा इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि यह निर्धारिती द्वारा दाखिल रिटर्न में आय को छिपाना है जो अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के प्रावधानों को आकर्षित करता है, न कि पिछले वर्ष के अंत के दौरान जिसके दौरान वास्तव में छिपाया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मैसूर बनाम सी वी बागलकोटी एंड संस और आयकर आयुक्त बनाम भान सिंह बूटा सिंह को संदर्भ दिया जा सकता है। भान सिंह बूटा सिंह के मामले में, इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए जो मुद्दा आया था, वह यह था कि क्या धारा 271 (1) (सी), जो 1 अप्रैल, 1964 से पहले थी, निर्धारिती के मामले

पर लागू होगी या क्या संशोधित प्रावधान जो 1 अप्रैल से लागू हुआ था, 1964 लागू होगा। उस मामले में, आकलन वर्ष 1963-64 था और करदाता ने 9 अप्रैल, 1964 को स्वैच्छिक रिटर्न दाखिल किया था। करदाता का रुख यह था कि चूंकि इसे वर्ष 1963-64 में छिपाया गया था, इसलिए धारा 271 (1) (सी), जैसा कि उस अवधि के दौरान थी, उसके मामले पर लागू होगी, न कि 1 अप्रैल, 1964 को अस्तित्व में आए मामले पर। यह माना गया था कि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जो देखा जाना है वह रिटर्न है और यह उस रिटर्न के आधार पर है कि कुछ परिणाम होते हैं। इस मामले के दृष्टिकोण पर, 9 अप्रैल, 1964 को लागू होने वाले कानून को जुर्माना लगाने में लागू किया गया था।

47. अब, विचारार्थ प्रश्न यह उठता है कि एक ओर संसद समय-समय पर अधिनियम में जुर्माने के उपबंधों में संशोधन करती रह सकती है और दूसरी ओर आईटीओ एक ही निर्धारिती अथवा विभिन्न निर्धारितियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत समय-समय पर नोटिस जारी करता रह सकता है। कानून बनाने और इसे एक विशेष तारीख से लागू करने की संसद की इच्छा समझ में आती है, लेकिन अदालतों को यह देखना होगा कि इसे समान रूप से उचित तरीके से इस तरह से लागू किया जाए कि यह संबंधित अधिकारियों द्वारा मनमाने या भेदभावपूर्ण अभ्यास द्वारा दुरुपयोग करने में सक्षम न हो जाए। विचार के लिए यह बिंदु दोहरे खतरे के सिद्धांत के उल्लंघन के बिंदु से अलग उठता है जिस पर इस निर्णय के बाद के भाग में चर्चा की जाएगी।

48. करदाता के मामले में आकलन का वर्ष 1963-64 है, जिस अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 271 (आई) (सी) में निहित दंड का कानून 1 अप्रैल, 1968 से लागू होने से अलग था। 1 अप्रैल, 1968 से लागू हुआ संशोधन आयकर **आयुक्त बनाम भान सिंह बूटा सिंह** मामले में इस अदालत के समक्ष विचार के लिए आया था। उपरोक्त मामले में करदाता की ओर से जो तर्क दिया गया था, उसे हमारे समक्ष नहीं उठाया गया है और उसमें दिए गए निर्णय को स्वीकार

करते हुए, करदाता का रुख यह है कि यह मूल रिटर्न है जिसके आधार पर जुर्माना लगाया जा सकता है। करदाता के अनुसार, यदि उस तारीख को लागू कानून के अनुसार जुर्माना लगाने के उद्देश्य से मूल रिटर्न की तारीख को निश्चित तारीख के रूप में नहीं लिया जाता है, तो पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी और करदाताओं को आईटीओ की इच्छा पर आराम करना होगा। किसी दिए गए मामले में, यदि दंड के प्रावधान को इस तरह से संशोधित किया जाता है कि यह संशोधन की तारीख से अधिक होगा, तो आईटीओ संशोधन की तारीख के बाद अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके एक ईमानदार निर्धारिती को परेशान करना चाहता है। उस स्थिति में, करदाता के लिए दो पाठ्यक्रम खुले होंगे, (1) करदाता धारा 148 के तहत नोटिस के अनुसरण में रिटर्न दाखिल नहीं करना चाहेगा और उस स्थिति में, वह अधिनियम की धारा 271 (1) (ए) के तहत जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा। यदि उसे पता चलता है कि उपरोक्त नोटिस के अनुसरण में रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना बहुत अधिक होगा, तो उसे यह रास्ता चुनना पड़ सकता है। इसलिए, उस स्थिति में, वह अधिनियम की धारा 271 (1) (ए) के तहत मूल रिटर्न दाखिल करने में पहले से ही किए गए जुर्माने के अलावा अतिरिक्त जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए मूल रिटर्न दाखिल करने के समय मौजूद कानून के अनुसार कम दर पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक अन्य मामले में, जिसमें करदाता ने 1 अप्रैल, 1968 के बाद अपना मूल रिटर्न दाखिल किया है, जब जुर्माना बहुत अधिक था, और यदि आईटीओ उसकी मदद करना चाहता है, तो वह 1 अप्रैल, 1976 के बाद अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी कर सकता है, और उस स्थिति में, उसे केवल आईटीओ के पक्ष में कार्य करने के कारण कम दंड के कानून का लाभ मिलेगा। यह स्पष्ट रूप से आईटीओ द्वारा करदाता को परेशान करने या उसकी मदद करने के लिए अधिनियम के विभिन्न संशोधनों के दुरुपयोग को दर्शाता है। कानून को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए और दुरुपयोग से बचने का एकमात्र संभव तरीका जुर्माना का आकलन करने के प्रयोजनों के लिए मूल रिटर्न दाखिल करने की तारीख तय करना होगा। मूल रिटर्न

कब दाखिल किया जाएगा, यह पता नहीं चलेगा कि संसद करदाता या राजस्व के पक्ष में जुर्माना लगाने के संबंध में कानून में कब संशोधन करना चाहेगी। यदि यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है, तो यह पूरी तरह से आईटीओ के हाथों में होगा, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है कि वे उन व्यक्तियों पर एक कठोर कानून लागू करें जिनके साथ वे खुश नहीं हैं और अधिनियम की धारा 148 के तहत एक नोटिस जारी करके अपने पसंदीदा लोगों के लिए उदार प्रावधानों को लागू करें। इसलिए, उपर्युक्त दृष्टिकोण में, यह मानना उचित और सामंजस्यपूर्ण होगा कि मूल रिटर्न दाखिल करने की तारीख जुर्माना लगाने के लिए कानून को नियंत्रित करेगी।

49. उपर्युक्त दृष्टिकोण से समर्थन प्राप्त करते हुए, अब मैं अगले बिंदु पर विचार करता हूँ कि अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) तैयार करते समय संसद किस बात को छिपाने पर विचार कर रही थी। धारा 271 (1) (सी) को शाब्दिक रूप से पढ़ने पर, मैं पाता हूँ कि आय के विवरण को छिपाना या ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत करना इस प्रावधान के तहत अपराध माना जाता है। किसी विशेष वर्ष के लिए, एक करदाता केवल एक बार अपराध कर सकता है जब वह अपनी आय का गलत विवरण प्रस्तुत करता है और वह रिटर्न दाखिल करके करता है। इसलिए, यदि उसे उसी वर्ष के लिए कई रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाता है और वह अपनी मूल स्थिति पर कायम रहता है, तो भी मेरे विचार से, वह बार-बार अपराध नहीं करेगा। अपराध वह होगा जो उसने पहली बार किया था जब उसने अपनी आय को छिपाते हुए रिटर्न दाखिल किया था और बाद में रिटर्न दाखिल करके, ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर, वह जो करता है वह यह है कि वह दृढ़ता दिखाता है कि उसने आय छिपाने का कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए, न तो कानून में, न ही अधिकार पर और न ही पहले सिद्धांतों पर यह कहा जा सकता है कि एक ही अपराध बार-बार किया जाता है। बेशक, इसी तरह के अपराध समय-समय पर किए जा सकते हैं। आयकर कानून के तहत प्रत्येक आकलन वर्ष एक अलग वर्ष होता है और इसलिए करदाता प्रत्येक वर्ष के लिए इसी तरह के अपराध कर सकता

है जिसके लिए वह धारा 271 (1) (सी) के तहत जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे उप-खंड (iii) के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि संबंधित वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करते समय प्रचलित होगा। इसी तरह, आईपीसी के उल्लंघन में किए गए अपराध के लिए, एक अभियुक्त केवल एक सजा के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन एक ही प्रावधान के तहत विभिन्न समय पर किए गए समान अपराधों के लिए वह अपराध करने के लिए जितनी बार भी करेगा, उतनी बार उत्तरदायी होगा।

50. इसलिए, मेरा दृढ़ मत है कि एक आकलन वर्ष के संबंध में आय के विवरण को छिपाने का अपराध तब पूरा होता है जब मूल या पहला रिटर्न किसी निर्धारित द्वाारा दाखिल किया जाता है जिसमें छिपाने का पता चलता है और उस अपराध को करदाता द्वारा दोहराया नहीं जाता है यदि उसे नोटिस के अनुसरण में समय-समय पर उस विशेष वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाता है। अधिनियम की धारा 148 मेरे उपरोक्त दृष्टिकोण को एक और बिंदु से और बल मिलता है जो बहस के समय विचार के लिए उठा था। प्रश्न यह है कि यदि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के अनुसरण में कोई अन्य रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो क्या वह मूल रिटर्न का स्थान लेगा या नहीं। राजस्व के लिए विद्वान वकील का रुख सकारात्मक था, जिसका अर्थ है कि अधिनियम के तहत सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए बाद की वापसी को देखा जाएगा। उपरोक्त उत्तर पर, एक और प्रश्न विचार के लिए आया और वह यह था कि यदि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के अनुसरण में दायर रिटर्न में, मूल रिटर्न में किए गए 1,00,000 रुपये को छिपाने के बजाय, करदाता 50,000 रुपये छिपाता है या कोई छिपाता नहीं है, फिर कानून में क्या स्थिति होगी। इस सवाल पर राजस्व विभाग के वकील ने अपने पहले के रुख में बदलाव किया और कहा कि भले ही करदाता पूरा ब्योरा देता है और कोई छिपाता नहीं है, लेकिन वह मूल रिटर्न के आधार पर जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा और आईटीओ या संबंधित आकलन प्राधिकरण बाद के रिटर्न को नजरअंदाज कर सकते हैं। मेरे विचार से यह पूरे मामले को फिर से दुविधा में डाल देता है और विभिन्न

आकलन प्राधिकारियों के लिए समय-समय पर जुर्माने के प्रावधानों का दुरुपयोग करने का विकल्प खुला रहेगा। कानून का यह इरादा कभी नहीं था।

51. मैं इस तथ्य से बेखबर नहीं हूँ कि अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत, एक करदाता को अपनी पिछली चूक का पता लगाने और मूल्यांकन करने से पहले किसी भी समय एक नया संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। केवल उस स्थिति में, गलत रिटर्न की मूल फाइलिंग अक्षम्य है और अधिनियम की धारा 271 के तहत उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आईटीओ अधिनियम की धारा 148 के तहत उसी या अलग-अलग करदाताओं को समय-समय पर नोटिस जारी करता रहेगा और हर बार आईटीओ को रिटर्न में से किसी एक को तय करने के लिए चुनना होगा। जुर्माने के प्रयोजनों के लिए एक करदाता पर देयता जो या तो एक करदाता की मदद कर सकती है या उसके खिलाफ जा सकती है। इसलिए, विभाग के वकील भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि जुर्माना तय करने के उद्देश्य से किस रिटर्न को रिटर्न के रूप में माना जाना चाहिए। संक्षेप में, राजस्व के लिए विद्वान वकील का जवाब यह आता है कि यह आईटीओ पर है कि वह किसी दिए गए करदाता के मामले में कोई रिटर्न ले और कानून के आधार पर जुर्माना लगाए क्योंकि यह उस रिटर्न को दाखिल करने की तारीख पर लागू था, चाहे वह मूल हो, दूसरा, तीसरा या चौथा वापसी।

52. न तो संसद ने सोचा था कि कानून की इस तरह से व्याख्या की जाएगी और न ही अदालतें मामले को अधर में छोड़ देंगी और सार्वभौमिक आवेदन के लिए एक दृढ़ दिशानिर्देश निर्धारित किया जाना चाहिए और, उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करने पर, मेरा दृढ़ विचार है कि उस तारीख को लागू कानून के अनुसार जुर्माना लगाने के लिए पहली रिटर्न दाखिल करने की तारीख को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस मामले को देखते हुए यदि कोई करदाता अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस का अनुपालन करते हुए अपनी मूल चूक का स्पष्ट

ब्यौरा देता है और बिना किसी बात के रिटर्न दाखिल करता है तो वह अपने मूल रिटर्न के आधार पर जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह, राजस्व को भी नुकसान नहीं होगा। इस व्याख्या के अनुसार, कम जुर्माना लगाने, फिर इसे बढ़ाने और फिर से कम करने के संसद के इरादे को आईटीओ द्वारा सामंजस्यपूर्ण रूप से रोकना होगा क्योंकि प्रत्येक मामले में लागू कानून उनकी सनक के अनुसार नहीं होगा, बल्कि कानून के अनुसार होगा जैसा कि यह मूल रिटर्न दाखिल करने की तारीख पर खड़ा था। चाहे उस समय जुर्माना कम या अधिक या फिर कम हो।

53. यह मामला असंगत नहीं है और मेरे उपरोक्त विचार के लिए, मुझे इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, मद्रास और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों के विभिन्न खंडपीठ निर्णयों से समर्थन मिलता है, जिसमें आयकर आयुक्त बनाम राम अचल राम सेवक, अतिरिक्त आयकर आयुक्त बनाम कृष्ण सुभाष करण , अतिरिक्त आयकर आयुक्त बनाम मेवा लाल संकठा प्रसाद, आयकर आयुक्त बनाम रामचंद्र कुंदनलाल सराफ, सुलेमानजी गनीभाई बनाम सीआईटी आईएलआर [1980] 373, गिफ्ट टैक्स आयुक्त बनाम सी मुथुकुमारस्वामी मुदलियार, आयकर आयुक्त बनाम जेकेए सुब्रमण्यम चेट्टियार, और अतिरिक्त आयकर आयुक्त बनाम आयकर डॉ. खुताबुद्दीनखान, जनरल मेडीसिन डॉक्टर / राजस्व के विद्वान वकील द्वारा विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए मेरे ध्यान में कोई मामला नहीं लाया गया है।

54. अब, दोहरे खतरे के बिंदु पर आते हुए, अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) पर ध्यान देना उचित होगा जो इस आशय की है - "अपनी आय के विवरण को छिपाया है या ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया है"। इस प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि जुर्माना लगाने का आधार रिटर्न दाखिल करना नहीं है, बल्कि आय को छिपाना या ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत करना है। दूसरे शब्दों में, जिस क्षण आय छिपाई जाती है या गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है, इस खंड के तहत जुर्माना लगाने का अपराध निर्धारित द्वारा किया

जाता है, लेकिन अपराध तब पूरा हो जाता है जब जिस दस्तावेज में छिपाया जाता है उसे आईटीओ के हाथों में रखा जाता है और यह रिटर्न दाखिल करके किया जाता है। इसलिए, जुर्माने के प्रयोजनों के लिए अपराध आईटीओ के समक्ष रिटर्न पेश किए जाने के साथ ही पूरा हो जाता है और यही कारण है कि सभी अदालतों ने माना है कि, अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत, आय को छिपाने या आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने का अपराध करदाता द्वारा रिटर्न दाखिल करके होता है। इस संबंध में अतिरिक्त आयकर आयुक्त, मैसूर बनाम सी वी बागलकोटी एंड संस, आयकर आयुक्त बनाम भान सिंह बूटा सिंह, आयकर आयुक्त बनाम गोपाल कृष्ण सिंघानिया, श्रीमती कमला वती बनाम आयकर आयुक्त (सेंट्रल), पटियाला को फिर से संदर्भ दिया जा सकता है। अमजद अली नजीर अली बनाम आयकर आयुक्त, | इसलिए, एक बार इस प्रावधान के तहत अपराध पूरा हो जाने के बाद, मेरे विचार से, अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) को पढ़ने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि जब भी किसी करदाता को उसी वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 148 के तहत नया रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, तो इसे बार-बार दोहराया जा सकता है और इसके विपरीत दृष्टिकोण लेने का मतलब यह होगा कि एक ही अपराध के लिए एक करदाता हो सकता है। दो बार सजा दी गई। यह न तो संसद का इरादा हो सकता है और न ही संभवतः अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) का अर्थ हो सकता है। जब राजस्व के वकील के समक्ष उपरोक्त बिंदु रखा गया, तो उन्होंने पहले की तुलना में बिल्कुल अलग रुख अपनाया और तर्क दिया कि यह दोहरे खतरे का मामला नहीं होगा या एक ही अपराध के लिए दो बार जुर्माना लगाया जाएगा क्योंकि विभाग जो कर सकता है वह एक ही वर्ष के लिए समय-समय पर दाखिल किए गए सभी रिटर्न पर जुर्माना लगाना है। कानून के तहत अधिकतम दंड की अनुमति है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं इस तर्क को समझने या सराहना करने में पूरी तरह से असमर्थ हूं। विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए इस तरह के निष्कर्ष को एन.ए. मालबारी और ब्रदर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप के फैसले से नहीं समझा जा सकता है। बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे, | इसके

विपरीत, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसार, एक ही छिपाने के संबंध में दंड के दो आदेश टिक नहीं सकते हैं और एक आदेश को वापस लेना होगा। इस प्रकार, एक ही वर्ष के लिए सभी रिटर्न ों पर जुर्माना लगाने का प्रश्न नहीं उठता है लेकिन केवल कानून के तहत अनुमेय अधिकतम दंड की प्राप्ति केवल उपर्युक्त निर्णय के आधार पर भी नहीं उठती है। उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के मामले में तथ्य यह था कि आईटीओ ने पाया कि 37,500 रुपये छिपाए गए थे और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन, जब अगले वर्ष के लिए करदाता का मामला आईटीओ के समक्ष आया और करदाता ने अपनी खाता पुस्तिकाओं को प्रस्तुत किया, तो आईटीओ ने पाया कि पिछले आकलन वर्ष के लिए 1,25,520 रुपये का लाभ हुआ था, जिसके बारे में मूल्यांकन पूरा हो गया था। इस प्रकार, उन्होंने भारतीय आईटी अधिनियम, 1922 की धारा 34 के तहत एक नोटिस जारी किया, जो अधिनियम की धारा 148 के बराबर है, और 1,25,520 रुपये की छिपी हुई आय पर 68,501 रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, आईटीओ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाने के उनके आदेश को वापस लेने में विफल रहा। जब 20,000 रुपये और 68,501 रुपये के जुर्माने के मामले ट्रिब्यूनल के समक्ष आए, तो ट्रिब्यूनल ने 20,000 रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया, लेकिन 68,501 रुपये के जुर्माने को बनाए रखा। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण के अनुसार, एक आकलन वर्ष के लिए केवल एक जुर्माना लगाया जा सकता है और अलग-अलग रिटर्न के आधार पर एक ही वर्ष के लिए एक से अधिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। इस मामले के तथ्यों पर जो सवाल हमारे सामने है, वह उस मामले में शामिल नहीं था। तदनुसार, मेरी राय है कि एक ही वर्ष के लिए दाखिल किए गए विभिन्न रिटर्न ों पर जुर्माना लगाना लेकिन कानून के तहत प्रदान की गई अधिकतम सीमा के अधीन वसूली योग्य नहीं है।

55. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि अधिनियम की धारा 271 (1) (iii) के प्रावधान इस मामले में लागू होंगे क्योंकि यह मौजूद था (यानी, इसके संशोधन से पहले

जो 1 अप्रैल, 1968 से लागू हुआ था) और जो 2 अप्रैल को पहली रिटर्न दाखिल करने के समय प्रचलित था, नतीजतन, इस प्रश्न का मेरा उत्तर, जिसे इस न्यायालय की राय के लिए संदर्भित किया गया है, सकारात्मक होगा, अर्थात्, निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ होगा। करदाताराजस्व से अपनी लागत का हकदार होगा।

मुख्य न्यायाधीश एसएस संधावालिया।

56. मुझे अपने विद्वान भाइयों, न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया और न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल द्वारा दर्ज किए गए स्पष्ट निर्णयों को पढ़ने का सौभाग्य मिला है, मैं न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल से पूरी तरह सहमत हूं और मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा